

केन्द्रीय मंत्रि-मंडल ने मध्यप्रदेश सहित 4 राज्यों की रेलवे मल्टी-ट्रेकिंग परियोजनाओं को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री मोदी का मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने माना आभार

भोपाल। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्रि-मंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मध्यप्रदेश सहित 4 राज्यों के 18 जिलों में रेलवे की 4 मल्टी-ट्रेकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मध्यप्रदेश को मिली इस सौगात के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार मानते हुए धन्यवाद किया है। पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार इन परियोजनाओं का उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारक परामर्श द्वारा मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाना है। ये



परियोजनाएं नागरिकों, वस्तुओं और सेवाओं को निर्बाध संपर्क प्रदान करेंगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रेलवे लाइन क्षमता में बढ़ोतरी से गतिशीलता बढ़ेगी जिससे भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और

सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा। मल्टी-ट्रेकिंग (पटरियों की संख्या बढ़ाना) से रेल परिचालन सुगम होगा और यात्रियों को सुविधा होगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप इन परियोजनाओं से क्षेत्र के लोगों का व्यापक विकास होगा, वे आत्मनिर्भर बनेंगे और उनके लिए रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

केन्द्रीय मंत्रि-मंडल समिति ने मध्यप्रदेश में 237 किलोमीटर लंबी इटारसी-भोपाल-बीना चौथी लाइन को और गुजरात एवं मध्यप्रदेश के बीच 259 किलोमीटर लंबी बड़ोदरा-रतलाम,

तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में वर्धा-भुसावल के बीच 314 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी लाइन को तथा महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ में 84 किलोमीटर लंबी गोंदिया-डोंगरगढ़ चौथी लाइन को मंजूरी दी गई है। कुल 24 हजार 634 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली ये परियोजनाएं 2030-31 तक पूरी होंगी। स्वीकृत मल्टी-ट्रेकिंग परियोजनाओं से लगभग 3 हजार 633 गांवों, जिनकी जनसंख्या लगभग 85 लाख 84 हजार है तथा 2 आकांक्षी जिलों विदिशा और राजनांदगांव तक संपर्क बढ़ेगा।

अवैध रूप से रह रहे विदेशियों के लिए स्वर्ग हो गया है भारत, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में की ऐसी टिप्पणी?



नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के शीर्ष न्यायालय ने सोमवार को एक अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विदेशी अवैध भारत में रह रहे हैं, उनके लिए ये देश स्वर्ग सा हो गया है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में एक रूसी नागरिक के साथ रह रहे एक इजरायली व्यक्ति को कड़ी फटकार लगाई। इसके साथ ही इजरायली व्यक्ति की दो नाबालिग बेटियों को रूस वापस भेजने से रोकने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

बता दें कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने ड्रॉर श्लोमी गोल्डस्टीन की ओर से एक याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इस याचिका में ड्रॉर श्लोमी गोल्डस्टीन ने दोनों नाबालिग लड़कियों के पिता होने का दावा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को प्रचार हित और तुच्छ मुकदमा बता दिया।

एचटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, याचिका की सुनवाई के दौरान दो न्यायाधीशों की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह देश हर तरह के लोगों के लिए स्वर्ग बन चुका है। कोई भी यहां आता है और हमेशा के लिए यहीं रह जाता है। वहीं, पीठ ने सवाल किया कि इजरायली नागरिक भारत में अपना गुजारा कैसे कर रहा है।

केन्द्रीय कैबिनेट ने Railway को लेकर किया बड़ा एलान, चार अहम प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी



मिली है।

वहीं इटारसी-चौथा-बीना के चौथे लेने को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग में केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आज की कैबिनेट बैठक में हमने चार नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक आज यानी मंगलवार को कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें चार नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही वडोदरा-रतलाम को तीसरी और चौथी लेन को मंजूरी मिली है। वहीं भुसावल-वर्धा तीसरी-चौथी लेन को भी मंजूरी

दी है। सात रेलवे कॉरिडोर कुल रेल यातायात का 41% हिस्सा वहन करते हैं। हमने हाल ही में इन कॉरिडोर को मजबूत करने और अधिक जोड़ने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। अब, हमने इन कॉरिडोर में न्यूनतम चार लेन और जहां संभव हो, छह लेन बनाने का निर्णय लिया है।

भगतान ने मुझसे कहा..., CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर ने क्या कहा?



नई दिल्ली (एजेंसी)। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंक दिया था। यह हादसा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। CJI पर हमला करने वाले वकील की पहचान 72 वर्षीय राकेश किशोर के रूप में हुई है। घटना के बाद राकेश को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया था। हालांकि, CJI गवई ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद आरोपी को रिहा कर दिया गया था।

दिवाली-छठ पर रेल यात्रियों को बड़ी सौगात, देश भर में चलेंगी 12000 ट्रेनें; मोदी कैबिनेट का अहम फैसला

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक की गई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे पहले रेल यात्रियों का ध्यान रखते हुए सरकार ने 12000 ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है।

रेलवे दिवाली-छठ जैसे त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए देश भर में 1200 स्पेशल दिवाली-छठ पर 12 हजार ट्रेनें चलाई जा रही है। इसके अलावा आज की कैबिनेट बैठक में चार नई रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है। सभी प्रोजेक्ट 3 से 5 साल में पूरे होंगे। इस बात की जानकारी केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है।

इस मामले में अमेरिका से आगे भारत-केन्द्रीय कैबिनेट के फैसलों के बारे में ब्रीफिंग

सिंगर जुबीन गर्ग की मौत का मामले में गहराया शक, CID ने सात लोगों को भेजा समन; केवल एक ने दिया जवाब



नई दिल्ली (एजेंसी)। मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में जांच जारी है। मामले की जांच कर रही सीआईडी ने सिंगरपुर में रहने वाले 8 भारतीयों को समन जारी किया था। हालांकि, केवल एक ही व्यक्ति ने इस समन का जवाब दिया और आज गुवाहाटी में सीआईडी के सामने उपस्थित हुए।

दरअसल, एनआरआई रुपकमल कलिता आज गुवाहाटी पहुंचे और सीआईडी के सामने पेश हुए। अब सिंगर की मौत के मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी।

कालिता रूप मूल रूप से असम के ही रहने वाले हैं।

आठ लोगों को जारी किया गया था नोटिस-इस मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने सिंगरपुर स्थित आठ प्रवासी भारतीयों को भारतीय उच्चायोग के माध्यम से 6 अक्टूबर तक रिपोर्ट करने को कहा था। इन सभी आठ प्रवासी भारतीयों को समन जारी किया गया था। जिसमें से केवल एक ही व्यक्ति ने इस समन का जवाब दिया है। अन्य सात लोगों द्वारा समन पर जवाब ना मिलने के बाद शक गहरा गया है।

सिंगरपुर में हुई थी सिंगर की मौत- गौरतलब है कि 52 साल के गायक जुबीन गर्ग की मौत पिछले महीने सिंगरपुर के एक याट में पार्टी के दौरान समुद्र में तैरने गए थे, जहां उन्हें पानी में औंधे मुंह तैरते हुए मृत पाए गए। बता दें कि 20 सितंबर से सिंगरपुर में होने वाले तीन दिवसीय नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे थे।



करते हुए केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब हम अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े माल दुलाई वाले देश बन गए हैं। हम 10 साल पहले जहां थे, उससे हमने बहुत बड़ी छलांग लगाई है।

चार नई परियोजनाओं का एलान- केन्द्रीय मंत्री

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज की कैबिनेट बैठक में हमने चार नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सात रेलवे कॉरिडोर कुल रेल यातायात का 41% हिस्सा वहन करते हैं। हमने हाल ही में इन कॉरिडोर को मजबूत करने और अधिक जोड़ने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। अब, हमने इन कॉरिडोर में न्यूनतम चार लेन और जहां संभव हो, छह लेन बनाने का निर्णय लिया है।

वहीं, इस ब्रीफिंग में केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे कई रेलवे परियोजनाएं आ रही हैं, रसद लागत कम हो रही है। जनसंख्या और अर्थव्यवस्था में हमारे जैसे कई देशों ने रेलवे पर जोर दिया है क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल है और लागत कम करने में भी मदद करता है।

सड़क से रेलिंग तोड़कर समुद्र में गिरी कार, ड्राइवर को किया गया रेस्क्यू



नई दिल्ली (एजेंसी)। मुंबई में एक अजीबोगरीब कार हादसे ने सभी के होश उड़ा दिए। समुद्र किनारे सड़क पर चलते हुए एक तेज रफतार कार अचानक रेलिंग तोड़ते हुए बाहर निकल गई। कार समुद्र में जा गिरी। इस हादसे के बाद ड्राइवर को किसी तरह से रेस्क्यू किया गया, लेकिन कार लहरों में बह गई।

यह मामला मुंबई की कोस्टल रोड पर सोमवार की रात हुआ। कार महालक्ष्मी से वर्ल्ड की तरफ जा रही थी, तभी ड्राइवर ने कार से संतुलन खो दिया और यह भीषण हादसा देखने को मिला।

महाराष्ट्र सुरक्षाबल के कर्मचारियों ने अपनी जान दांव पर लगाकर ड्राइवर को समुद्र से बाहर निकाला। कार हादसे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि, पुलिस को शक है कि ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने ड्राइवर के खून का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा है।

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, ड्राइवर ने अचानक कार से नियंत्रण खो दिया और कार रेलिंग तोड़ते हुए 30 फीट की ऊंचाई से समुद्र में गिर गई। स्क्व ने कार को गिरते देखा और फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। ड्राइवर को किसी तरह समुद्र से बाहर निकाला गया। इस दौरान उसे कुछ चोटें आई हैं।

ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। वर्ल्ड पुलिस स्टेशन ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है।

जब तक आजादी नहीं मिलेगी..., पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस में IED ब्लास्ट; विद्रोहियों ने बताई हमले की वजह



नई दिल्ली (एजेंसी)। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मंगलवार को जाफर सुल्तानकोट क्षेत्र में एक तात्कालिक

एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाकर एक बार फिर विस्फोट किया गया। इसमें कई लोग घायल हो गए।

क्रेटा की ओर जा रही इस ट्रेन पर सिंध-बलूचिस्तान सीमा के पास

विस्फोटक उपकरण से हमला किया गया। इसके कारण कम से कम छह डिव्बे पटरी से उतर गए। यह इस साल मार्च के बाद से जाफर एक्सप्रेस पर हुआ ताजा हमला है।

बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।

उन्होंने दावा किया गया कि ट्रेन में पाकिस्तानी सेना के जवान यात्रा कर रहे थे। समूह ने अपने बयान में कहा, यह हमला तब किया गया जब पाकिस्तानी सेना के जवान ट्रेन में सवार थे। विस्फोट के

परिणामस्वरूप कई सैनिक मारे गए और घायल हुए साथ ही ट्रेन के छह डिव्बे पटरी से उतर गए।

हालांकि, अभी तक किसी की मौत की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

बलूच विद्रोहियों का दावा- बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने अपने बयान में यह भी कहा कि ऐसे हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक बलूचिस्तान की आजादी नहीं मिल जाती। घटनास्थल पर बचाव दल और सुरक्षा बल पहुंच चुके हैं, और राहत कार्य

चल रहा है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में घायल लोगों को दिखाया गया है, जो इस हमले की गंभीरता को दर्शाता है।

जाफर एक्सप्रेस क्रेटा से पेशावर तक चलती है। इस साल कई बार निशाना बन चुकी है। मार्च में सबसे घातक हमला हुआ था, जब बोलन क्षेत्र में ट्रेन को हाइड्रोजन कर लिया गया था, जिसमें 21 यात्रियों और चार सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई थी। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने 33 आतंकवादियों को मार गिराया था।

उत्तर कोरिया के साथ नजदीकी बढ़ाने में जुटा ड्रैगन, इस वजह से 6 साल बाद किम जोंग उन से मिलेंगे चीनी पीएम

नई दिल्ली (एजेंसी)। चीन और उत्तर कोरिया के रिश्ते एक बार फिर परवान चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने चीन का दौरा किया था। वहीं, अब चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग भी उत्तर कोरिया जाने की तैयारी कर रहे हैं। 2019 के बाद यह पहली बार है, जब इतने बड़े पद पर मौजूद कोई चीनी नेता उत्तर कोरिया का रुख करने वाला है।

चीनी विदेश मंत्रालय ने ली कियांग के दौरे



की जानकारी देते हुए कहा कि गुरुवार से शनिवार तक चीनी पीएम अन्य अधिकारियों

क साथ उत्तर कोरिया जाएंगे। इस दौरान चीनी पीएम उत्तर कोरिया की सत्ताधारी पार्टी के 80वें सालगिरह समारोह में हिस्सा लेंगे।

रूस के पूर्व राष्ट्रपति का भी दौरा-चीन लंबे समय से उत्तर कोरिया का अहम साझेदार रहा है। वहीं, उत्तर कोरिया ने रूस के साथ भी अपने रिश्ते सुधारे हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद करने के लिए किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया से बड़ी संख्या में सैनिक भेजे हैं। ऐसे में सत्ताधारी

पार्टी की 80वीं सालगिरह पर रूस भी पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव को उत्तर कोरिया भेजने की भेजने वाला है।

चीनी विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान- चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, चीन और उत्तर कोरिया पड़ोसी होने के साथ-साथ पारंपरिक दोस्त भी हैं। यह चीनी सरकार की अहम रणनीतिक नीति है। खासकर चीनी सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर कोरिया के साथ रिश्ते मजबूत करने का समर्थन करती है।

फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार का एलान, अमेरिका के इन तीन वैज्ञानिकों को मिला प्राइज

Nobel Prize in Physics 2025



मैक्रोस्कोपिक क्वांटम, मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटिजेशन की खोज के लिए दिया गया है।

कितनी मिलती है धनराशि- बता दें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा हर साल फिजिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट खोजों के लिए दिया जाता है। नोबेल प्राप्त करने वाले वैज्ञानिकों को इनाम के तौर पर कुल 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन (यानी 12 मिलियन डॉलर) की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है, अगर एक जैसी खोज के लिए कई वैज्ञानिकों को साझेदारी में नोबेल प्राइज मिलता है तो ऐसी दशा में पुरस्कार राशि को सभी में बांट दिया जाता है।

नई दिल्ली (एजेंसी)। साल 2025 के लिए नोबेल पुरस्कारों का एलान शुरू हो गया है। सोमवार को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल के एलान के बाद मंगलवार को नोबेल समिति ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की है।

साल 2025 के लिए भौतिकी का नोबेल 3 वैज्ञानिकों जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनिस के नाम रहा। इन तीनों को ये पुरस्कार विद्युत परिपथ में

अमेरिका में भारतीय की हत्या करने वाला आरोपी रिचर्ड गिरफ्तार, पुलिस ने बंदूक किया बरामद



नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका में पिछले दिनों एक भारतीय की गोली मारकर हत्या कर गई। इस घटना ने देश विदेश से अमेरिका जा रहे लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मृतक की पहचान चंद्रशेखर पोल के तौर पर हुई थी, जो अपनी नौकरी कर रहा था। अब खबर है कि चंद्रशेखर की हत्या करने वाले 23 वर्षीय रिचर्ड फ्लोरेज को वहां के अधिकारियों ने टेक्सस से गिरफ्तार किया है। दरअसल हैदराबाद के रहने वाले एक छात्र की अमेरिका के टेक्सस में हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से भाग खड़ा हुआ।

जिसके बाद अधिकारी उसकी तलाश कर रहे थे।

कहां हुई घटना- बता दें कि ये घटना शुक्रवार की है। शुक्रवार रात ईस्टचेस पार्कवे स्थित फोर्ट वर्थ के एक गैस स्टेशन पर भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी की तलाश कर रही थी। अब सोमवार को पुलिस ने 23 साल के रिचर्ड फ्लोरेज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक गाड़ी और एक बंदूक बरामद की है।

मृतक के अवशेषों को लाया जाएगा भारत- गौरतलब है कि इस घटना भारत में भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ह्यूस्टन स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने कहा कि वे मृतक के अवशेषों को स्वदेश वापस लाने में सहायता के लिए हैदराबाद में उसके परिवार के संपर्क में हैं। अवशेषों को भारत वापस लाने और पोल के शोकाकुल परिवार की सहायता के लिए एक GoFundMe अभियान भी शुरू किया गया है।

ट्रंप को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने चला नया दांव, डील को बेकरार शहबाज-मुनीर ने शिप से US भेजा ये सामान



नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकियां लगातार परवान चढ़ रही हैं। पाकिस्तान के आलाकमान अमेरिका को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पाक आर्मी चीफ असोम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हाल ही में अमेरिका के दौरे पर गए थे। वहीं, अब दोनों देश रेयर अर्थ मिनरल को निकालने की तैयारी कर रहे हैं।

पाकिस्तानी समाचार चैनल डॉन के अनुसार, अमेरिका और पाकिस्तान ने रेयर अर्थ मिनरल के निर्यात पर हुए समझौते को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिका के साथ डील पक्की करने के लिए पाकिस्तान ने रेयर अर्थ मिनरल के सैंपल के तौर पर पहली खेप को खाना कर दिया है।

पाकिस्तान में निवेश करेगा अमेरिका- सितंबर में यूएस स्ट्रैटजिक मेटल्स ने पाकिस्तान के साथ एक रूथ पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत स्क्रू ने पाकिस्तान में मिनरल प्रोसेसिंग और विकास कार्यों के लिए 500 मिलियन डॉलर

का निवेश करने की योजना बनाई थी।

क्या है पाकिस्तान का प्लान- बता दें कि रेयर अर्थ मिनरल न सिर्फ औद्योगिक विकास में मददगार है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिये से भी बेहद अहम है। ऐसे में पाकिस्तान भी रेयर अर्थ मिनरल की वैश्विक सप्लाई चेन में शामिल होना चाहता है, जिसके लिए पाक अमेरिका को खुश करने की कोशिश में लगा है।

पहली खेप में क्या भेजा- पाकिस्तान ने अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल की जो पहली खेप भेजी है, इसे फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया गया है।

अगर टैरिफ न लगाता तो..., ट्रंप ने US को बताया शांतिदूत; Tariff थोपने के फैसले को ऐसे किया जस्टिफाई



नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार दावा किया है कि उन्होंने विश्व में सात देशों के बीच जारी संघर्ष को समाप्त कराया। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत-पाक का संघर्ष भी उन्होंने ही समाप्त कराया। हालांकि, भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में किसी भी तीसरे की मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं है।

वहीं, जब उनसे टैरिफ के बारे में पूछा गया, तो इस स्थिति में उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास टैरिफ लगाने

का अधिकार नहीं होता, तो सात में से कम से कम चार युद्ध चल रहे होते। उन्होंने दावा किया कि ये टैरिफ ही इस साल की शुरुआत में सशस्त्र संघर्ष के दौरान दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच युद्धविराम समझौते का कारण बने।

टैरिफ ने अमेरिका को बनाया शांतिदूत- एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण अमेरिका अब शांतिदूत बना है। इतना ही नहीं, टैरिफ के कारण अमेरिका को सैकड़ों अरब डॉलर की कमाई हो रही है।

भारत-पाक संघर्ष विराम का क्रेडिट लेते रहे हैं ट्रंप- गौरतलब है कि ये कोई पहला मौका नहीं है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस प्रकार का दावा किया है। इससे पहले भी कई मौकों पर ट्रंप ने ये दावा किया है। बता दें कि 10 मई 2025 को जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि वाशिंगटन की मध्यस्थता में रात भर चली लंबी बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं।

कैलीफोर्निया में हेलीकॉप्टर क्रैश होकर हाईवे पर गिरा, 3 लोग घायल



नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से सनसनी फैल गई। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा सोमवार की शाम को कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में हुआ। घटना की सूचना मिलते ही फायर विभाग के लोग मौके पर पहुंचे।

हवा में उड़ान भरने के दौरान हेलीकॉप्टर अचानक क्रैश हो गया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आसमान में आग का गोला बनने के बाद हेलीकॉप्टर हाईवे पर जा गिरा।

क्रैश की वजह साफ नहीं- कैलिफोर्निया में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस मुहैया करवाता था। हेलीकॉप्टर ने पास के ही एक अस्पताल से उड़ान भरी थी। वहीं, हेलिकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ? यह अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

हाईवे पर गिरा हेलीकॉप्टर- हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सैक्रामेंटो की मेयर केविन के अनुसार, नेशनल हाईवे 50 पर हेलीकॉप्टर गिरा था। यह बेहद भयानक घटना थी। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

कौन हैं रागिनी दास? गूगल ने 2013 में कर दिया था रिजेक्ट, अब बनी स्टार्टअप हेड



नई दिल्ली (एजेंसी)। गूगल कंपनी में नौकरी पाना कई लोगों का सपना होता है। वहीं, गुरुग्राम की रहने वाली रागिनी दास को

भी उनकी ड्रीम जॉब मिल चुकी है। गूगल इंडिया ने रागिनी को स्टार्टअप हेड नियुक्त किया है। मगर, क्या आप जानते हैं कि 2013 में इसी गूगल कंपनी ने रागिनी को रिजेक्ट कर दिया था।

रागिनी दास ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए अपने सफर की दिलचस्प कहानी सुनाई है। गूगल इंडिया से पहले रागिनी कई बड़ी कंपनियों का हिस्सा रह चुकी हैं। इसके अलावा वो leap.club की को-फाउंडर भी हैं।

रागिनी की सक्सेस स्टोरी- गूगल इंडिया में

अपनी नई जॉब पर बात करते हुए रागिनी ने बताया कि 2013 में गूगल ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था और उसी कंपनी ने उन्हें स्टार्टअप हेड के तौर पर हायर किया है।

चेन्नई से पूरी की स्कूल की पढ़ाई- रागिनी दास का जन्म गुरुग्राम में हुआ था। उन्होंने चेन्नई के चेन्नैनाड विद्याश्रम से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। वहीं, लैंकेस्टर विश्वविद्यालय से बिजनेस में स्नातक के दौरान वो चेन्नई विद्याश्रम की कल्चरल सचिव भी रह चुकी हैं। ग्रेजुएशन के समय भी उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक समेत कई बड़े संस्थानों में काम

किया। इस दौरान उन्होंने भारत में मार्केट रिसर्च समेत कई बिजनेस प्लान भी विकसित किए।

जोमैटो में 6 साल तक की नौकरी- 2012 में रागिनी दास ट्राइडेंट ग्रुप इंडिया का हिस्सा बनीं और बाद में उन्हें यूरोप और अमेरिका में मार्केटिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2013 में रागिनी को जोमैटो कंपनी का सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर नियुक्त किया गया। 6 साल तक इस कंपनी में नौकरी के दौरान रागिनी ने अकाउंट मैनेजर और एरिया सेल्स मैनेजर के पद पर काम किया।

गले में धंसी हुई चाकू और खून से लथपथ होकर अकेले अस्पताल पहुंचा शख्त, डॉक्टर-नर्स देखकर हुए सन्न



नई दिल्ली (एजेंसी)। केरल के कासरगोड में एक चौकाने वाला मामला सामने आया है। लड़ाई के दौरान एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में लहलुहान पीड़ित जब अस्पताल पहुंचा, तो उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। व्यक्ति के गले में चाकू धंसी थी और खून बह रहा था। उसे देखते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। पीड़ित की पहचान 36 वर्षीय अनिल कुमार के रूप में हुई है। अनिल ने पुलिस को बताया कि उसकी किसी बात पर एक व्यक्ति से बहस हो गई थी, जिसके बाद आरोपी ने अनिल को चाकू घोंप दी।

क्या है पूरा मामला- यह मामला रविवार की रात का है। अनिल कुमार कासरगोड में ही मछली व्यापारी का काम करते हैं। अनिल के अनुसार, रविवार की रात को उसे एक फोन आया और आरोपी ने वित्त झगड़े के कारण उसे सीधनगोली गांव आने के लिए कहा। जब अनिल सीधनगोली पहुंचा, तो आरोपी ने उसपर हमला कर दिया। अनिल को चाकू भोंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है, जिसमें वो दर्द से कराहते नजर आ रहा है। हमले के बाद अनिल फौरन मंगलुरु स्थित अस्पताल के लिए भागा। इस दौरान चाकू उसके गले में ही फंसी थी।

बंगाल में BJP सांसद पर हमले का मामला गरमाया, लोकसभा सचिवालय ने गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी



नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर हमले का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने हमले की सख्त आलोचना की है। वहीं, अब लोकसभा सचिवालय ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है।

लोकसभा सचिवालय ने गृह मंत्रालय से पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगने को कहा है। इसके लिए बंगाल सरकार के पास 3 दिन का समय है।

लोकसभा सचिवालय ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार से तीन दिन के भीतर तथ्यात्मक नोट मांगा

जाए। बता दें कि, जलपाईगुड़ी में खगेन मुर्मू पर हुए हमले के दौरान उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। इस हमले में उनके सिर पर चोट लगी है और आंख बाल-बाल बची है।

बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू बाढ़ प्रभावित इलाके के दौर पर गए थे। वो आपदा में बेघर हुए लोगों को राहत सामग्री देकर लौटे थे, तभी कुछ लोगों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। इस दौरान उनकी गाड़ी पर पत्थर, जूते, चप्पल और डंडे बरसाए गए। हमले में गाड़ी के शीशे भी चकनाचूर हो गए। इस दौरान खगेन मुर्मू के सिर में गंभीर चोट लग गई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है और उनका इलाज चल रहा है।

खगेन मुर्मू पर हमले के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी ने हमले के पीछे ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का हाथ बताया है।

केवल दिल्ली में बैठे नेताओं को दिक्कत... बिहार SIR पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या कहा?



नई दिल्ली (एजेंसी)। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद चुनाव आयोग ने अंतिम लिस्ट जारी कर दी थी। SIR का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा हुआ है। फाइनल लिस्ट जारी करने के बाद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भी इसकी जानकारी दे दी है। आयोग ने कहा है कि जो अंतिम मतदाता सूची जारी की गई है, उसमें कई नाम जोड़े गए हैं।

चुनाव आयोग ने कहा कि फाइनल लिस्ट में जोड़े गए नामों में नए वोटर और कुछ पुराने वोटर शामिल हैं। आयोग ने SIR को लेकर राजनीतिक दलों के आरोपों पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा किया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि किसी भी प्रभावित या डिलीट नाम वाले वोटर ने अब तक कोर्ट का रुख

नहीं किया।

कोर्ट ने मांगी मतदाताओं की जानकारी- आयोग ने कहा कि केवल दिल्ली में बैठे नेता और एनजीओ ही मुद्दा उठा रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि आयोग गुरुवार तक बाहर रखे गए मतदाताओं की जानकारी प्रस्तुत करेगा और इसी दिन एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आगे की सुनवाई होगी।

पीठ ने कहा कि अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या से ऐसा प्रतीत होता है कि ड्राफ्ट रोल के मुकाबले संख्या में वृद्धि हुई है। इसलिए किसी भी भ्रम से बचने के लिए अतिरिक्त मतदाताओं की पहचान का खुलासा किया जाना चाहिए। अब शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई को गुरुवार के लिए लिस्ट कर दिया है।

बता दें कि 30 सितंबर को एसआईआर से पहले बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7.89 करोड़ थी, लेकिन अंतिम मतदाता सूची में यह घटकर 7.42 करोड़ हो गई। चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को बिहार में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। बिहार की 243 सीटों पर 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी।

सबरीमाला मंदिर में चोरी हुए सोने का खुल गया राज, इस काम में किया जाना था इस्तेमाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। सबरीमाला अय्यप्पन मंदिर में सोने की कथित चोरी के मामले में नया मोड़ शामे आया है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, मंदिर के प्रायोजक, उन्नीकृष्णन पोद्दी मंदिर के बचे हुए सोने का इस्तेमाल एक लड़की की शादी में करना चाहते थे। इस संबंध में उन्होंने 9 दिसंबर, 2019 को त्रावणकोर देवस्वाम बोर्ड (टीडीबी) को एक चिट्ठी लिखकर बचे हुए सोने का इस्तेमाल करने के बारे में जानकारी दी थी।

मंदिर के प्रायोजक उन्नीकृष्णन पोद्दी ने बताया था कि मंदिर के मुख्य द्वार और द्वारपालक पर सोने की प्लेटों का काम पूरा होने के बाद भी उनके पास कुछ अतिरिक्त सोना बचगया है। जिसके सही उपयोग के लिए पोद्दी ने टीडीबी से सलाह मांगी



थी। साथ ही उन्होंने पत्र में ये भी लिखा था कि वो ईद बचे हुए सोने से एक लड़की की शादी कराना चाहते हैं।

क्या है पूरा विवाद- पूरा विवाद सबरीमाला अय्यप्पन मंदिर के गर्भगृह के बाहर द्वारपालकों की मूर्तियों पर सोने की प्लेट चढ़ने को लेकर शुरू हुआ। इन मूर्तियों पर सोने की चोरी और गड़बड़ी के आरोप लगाए गए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि टीडीबी ने इन शीटों को

मरम्मत के लिए हटाकर उन्नीकृष्णन पोद्दी नाम के प्रायोजक को सौंप दिया था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कथित सोना चोरी को लेकर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली केरल सरकार से जवाबदेही की मांग की है और घटना पर संदेह व्यक्त किया है। केरल हाईकोर्ट ने इस संबंध में विजिलेंस जांच का आदेश दिया। जिसमें मंदिर से 4154 किलोग्राम सोने की कथित चोरी की बात सामने आई। जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ थी।

इस हफ्ते की शुरुआत में, अदालत ने सोने की प्लेटों के वजन में कमी से जुड़ी कथित गड़बड़ी की जांच के लिए एक विशेष जांच दल के गठन का निर्देश दिया था।

गोवा को डर और भ्रष्टाचार से मुक्त करने का किया आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने वादा



नई दिल्ली (एजेंसी)। गोवा की सड़कों की हालत देखकर किसी का भी दिल दुख जाएगा। हर गली-मोहल्ले में टूटी सड़कें, गड्डों से भरे रास्ते और बरसात में कीचड़ से लबालब गलियां यही है बीजेपी के 13 साल के राज की सच्चाई। हर साल बजट में हजारों करोड़ रुपये पास होते हैं, लेकिन सड़कें क्यों नहीं बनती? आखिर वह पैसा कहाँ चला जाता है?

इसी सवाल का जवाब मांगने के लिए आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा सिग्नेचर अभियान चलाया। गोवा के कुल 3.5 लाख परिवारों में से 1 लाख परिवारों ने इस अभियान में हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सड़कें तुरंत ठीक करने की मांग की। सोमवार को इन्हीं चिट्ठियों से भरा ट्रक मुख्यमंत्री को सौंपा गया। यह कोई साधारण विरोध नहीं है, यह हर उस गोवावासी

की आवाज़ है जो अब और चुप नहीं रहना चाहता। भ्रष्टाचार इतना गहरा है कि जो सड़कें बनती भी हैं, वे कुछ ही दिनों में फिर से टूट जाती हैं। जनता को झूठे वादों और अधूरे कामों से बहकाया गया, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने गांव-गांव में 18,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण करवाया है। वहां सख्त नियम है, अगर सड़क पांच साल से पहले खराब हुई, तो ठेकेदार को अपने पैसे से मरम्मत करनी होगी। यही होती है जिम्मेदार सरकार।

गोवा एक अमीर राज्य है, फिर भी आज भी लोगों को पीने का पानी टैंकों से मिलता है। आम आदमी पार्टी के सिर्फ दो विधायक हैं, फिर भी लोग चंदा इकट्ठा करके मोहल्ला क्लीनिक खोल रहे हैं। वहीं बीजेपी के पास हजारों करोड़ हैं, लेकिन जनता के लिए न अस्पताल बने, न स्कूल सुधरे, न सड़कें ठीक हुईं। क्योंकि बीजेपी को जनता की नहीं, सिर्फ सत्ता और पैसे की चिंता है।

आज गोवा की जनता डरी हुई है। अपराध बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, और सरकार पर सवाल उठाने वालों पर हमले हो रहे हैं। समाजसेवी रमा कांकणकर पर हमला सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने सरकार की आलोचना की। आम आदमी पार्टी ने इस अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आवाज़ उठाई।

hindkush.in

24x7 News portal

हिन्दकुश

info@hindkush.in

दैनिक
हिन्दकुश

सर्वे भवन्तु सुखिनः

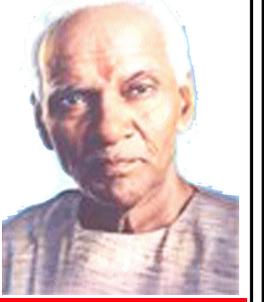
उजैन, इंदौर, भोपाल से प्रकाशित

jagrayam.com

online news magazine

जाग्रयाम

info@jagrayam.com



हिन्दकुश

हिन्द : भारत कुश : पवित्र तृण

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भागभवेत्
सभी सुखी हो, सभी निरोगी रहे, सभी का शुभ हो, कोई भी दुखी न हो।

विक्रम संवत् 2079 शुक्ल प्रतिपदा

संपादकीय

भारत देश संस्कृति, भाषाओं, उपनिषद साहित्य से पिरोई ऐसी खूबसूरत माला है जो...



मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है, जिनके द्वारा मन की बात बताई जाती है। किसी भाषा की सभी ध्वनियों के प्रतिनिधि स्वर एक व्यवस्था में मिलकर एक सम्पूर्ण भाषा की अवधारणा बनाते हैं। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान-प्रदान का माध्यम कहा जा सकता है।

साथियों बात अगर हम भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची की करें तो, इसमें 22 भाषाएँ तो आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं ही पर यदि सब गिनी जाएँ तो हमारे देश में 30 से अधिक भाषाओं के साथ 100 से अधिक क्षेत्रीय भाषाएँ भी हैं। अनुसूचित भाषाएँ 1) असमिया, (2) बंगला, (3) बोडो, (4) डोगरी, (5) गुजराती, (6) हिंदी, (7) कन्नड़, (8) कश्मीरी, (9) कोंकणी, (10) मैथिली, (11) मलयालम, (12) मणिपुरी, (13) मराठी, (14) नेपाली, (15) उड़िया, (16)

पंजाबी, (17) संस्कृत, (18) संथाली, (19) सिंधी, (20) तमिल, (21) तेलुगू और (22) उर्दू।

साथियों बात अगर हम हिंदी भाषा की करें तो, यह विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। जो हमारे पारम्परिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही ग्यारह राज्यों और तीन संघ शासित क्षेत्रों की भी प्रमुख राजभाषा है। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य इकतीस भाषाओं के साथ हिंदी का एक विशेष स्थान है।

साथियों बात अगर हम सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित भाषाओं की करें तो यह भारतीयता की खूबसूरती है कि, इतनी भाषाओं के बीच भारत अपनी खूबसूरती बिखेर रहा है। यह भारतवर्ष के लिए आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि मुख

से उच्चारित भाषा के आदान-प्रदान से ही ज्ञान की ज्योत प्रज्वलित होती है। हमें इन सभी भाषाओं, जो अनुसूचित नहीं भी हैं, उसका संरक्षण करना जरूरी है।

साथियों बात अगर हम अंग्रेजी भाषा की करें तो आज के आधुनिक डिजिटलाइजेशन युग में अंग्रेजी बोलचाल का फैशन सा हो गया है, जो मातृभाषा में बात करता है उसे हम पुराने जमाने की सोच का दर्जा देते हैं। हम अपने सामाजिक भाषाओं की विलुप्तता को प्रोत्साहन देने का काम करते हैं जिसे रोकना होगा।

क्योंकि हमारे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश सहित अनेक प्रशासनिक व्यक्तित्व की प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में ही हुई है। इसलिए भारतीय भाषाएँ भारत रूपी माला में पिरोए वह मोती हैं जिसके प्रकाश से ही आज भारत विश्व में जगमगा रहा है। इसलिए भारतीय भाषाओं का

वैज्ञानिक और तकनीकी स्तर पर संरक्षण जरूरी है।

साथियों बात अगर हम भारतीय भाषाओं के संरक्षण में माननीय उपराष्ट्रपति के एक भारतीय भाषादिवस के अवसर पर वर्चुअल संबोधन की करें तो पीआईबी की प्रेसविज्ञप्ति के अनुसार, उपराष्ट्रपति ने इसका उल्लेख किया कि भाषा न केवल हमारी पहचान का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। इसके लिए, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में होने की जरूरत को रेखांकित किया, जिसकी परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है और आखिरकार उच्चतर व तकनीकी शिक्षा तक इसे विस्तारित किया जाना है। उन्होंने व्यापक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली में भी सुधार का सुझाव दिया।

भारतीय वायु सेना दिवस



भारतीय वायु सेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसी मौके को याद करते हुए हर साल इस दिन को भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वायु सेना दिवस को आधिकारिक तौर पर सर्वप्रथम 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय साम्राज्य की सहायक वायु सेना के रूप में मनाया गया था। वर्ष 2017 में, केंद्रीय वायु सेना 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना की 85वीं वर्षगांठ को पूरे देश के विभिन्न हवाई स्टेशनों पर बहुत उत्साह के साथ मनाया। ऑपरेशन राहत और ऑपरेशन मेघदूत जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण अभियानों में तैनात विमान और हेलीकाप्टर भी प्रदर्शित किये जाते हैं। इसके साथ-साथ, विभिन्न अभियानों के लिए तैयार किये गए नए विमान भी प्रदर्शित किए जाते हैं, साथ ही इसकी विशेषताओं और इसके उद्देश्यों को भी समझाया जाता है।

इतिहास

वर्ष 1932 में इसकी स्थापना के बाद से ही भारतीय वायु सेना की उपलब्धियों का उल्लेखनीय इतिहास रहा है। भारतीय हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रखने और संघर्ष के दौरान हवाई युद्ध का आयोजन करने के अपने प्राथमिक उद्देश्य का पालन करते हुए, भारतीय वायु सेना को पाकिस्तान के साथ चार युद्ध और चीन के साथ एक युद्ध में शामिल किया गया है। वायु सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में भी जापानी सेना को बर्मा में रोककर सक्रिय भूमिका निभाई थी। वायु सेना के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में ऑपरेशन विजय (गोवा का दावा करने के लिए), ऑपरेशन मेघदूत (विवादित कश्मीर क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर को पकड़ने के लिए), ऑपरेशन कैक्टस (मालदीव में बचाव अभियान), ऑपरेशन पोमलाई (श्रीलंका में जाफना शहर के घेरे वाले शहर पर हवाई-

ड्रॉप की आपूर्ति के लिए) और ऑपरेशन राहत (उत्तराखंड में फ्लैश बाढ़ से पीड़ित लोगों के बचाव और राहत) शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय वायु सेना संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में भी शामिल है। भारतीय वायु सेना में लगभग 1,70,000 कर्मियों की ताकत है और 1,400 से अधिक विमान हैं और इसे दुनिया के अग्रणी वायु सेना में से एक माना जाता है। भारतीय क्षेत्रों को सभी जोखिमों से बचाना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करना इसकी जिम्मेदारी है।

आयोजन

8 अक्टूबर को परेड के साथ वायु सेना उत्सव की शुरुआत होती है। सभी वायु सेना स्टेशन अपने हवाई अड्डों पर अपने संबंधित परेड आयोजित करते हैं। पारंपरिक सैन्य परेड एक ही प्रोटोकॉल का अनुसरण करते



हैं। बगल की आवाज के साथ दाहिनी ओर से परेड की शुरुआत होती है। आकस्मिक रूप से दोनों उड़ानों में से प्रत्येक में चार स्क्राइड शामिल होते हैं और इसकी कमान एक विंग कमांडर के हाथ में होती है। पूरे उत्सव में परेड के साथ एक बैंड होता है। एक बार जब परेड ग्राउंड पर परेड का जुलूस होता है, तो सभी उपस्थित लोगों के सम्मान में सभी वर्दीधारी वायु सैनिक परेड की सलामी देते हैं।

आदर्श वाक्य

भारतीय वायु सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना है। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित हिंडन वायु सेना स्टेशन एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है। भारतीय वायु सेना के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक यह अपने ध्येय वाक्य नभ-स्पृशं

दीप्तम के मार्ग पर चल रहा है। इसका अर्थ है गर्व के साथ आकाश को छूना। वायु सेना के इस ध्येय वाक्य को भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। यह महाभारत के महायुद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है। इसी आदर्श वाक्य के साथ भारतीय वायु सेना अपने कामों को अंजाम देती है।

वायु सेना ध्वज

वायु सेना ध्वज, वायु सेना निशान से अलग, नीले रंग का है जिसके शुरुआती एक चौथाई भाग में राष्ट्रीय ध्वज बना है और बीच के हिस्से में राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों अर्थात्? केसरिया, श्वेत और हरे रंग से बना एक वृत्त (गोलाकार आकृति) है। यह ध्वज 1951 में अपनाया गया था।

फेस्टिव सीजन में राहत! सितंबर में थाली के दाम लुढ़के; सब्जियों और दालों की कीमतों में भारी गिरावट का असर



नई दिल्ली (एजेंसी)। क्रिसल की मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, क्रमोडिटी की कीमतों में भारी गिरावट के

बीच सितंबर के दौरान घर में बनी शाकाहारी और मांसाहारी थाली की कीमत में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में क्रमशः 10 प्रतिशत और 6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सब्जियों और दालों की कीमतों में भारी गिरावट के कारण शाकाहारी थाली की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स द्वारा स्टॉक की डंपिंग के कारण आलू की कीमतों में 31 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि अधिक सप्लाई के कारण

टमाटर की कीमतों में सालाना आधार पर 8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

प्याज की कीमतों में गिरावट- रिपोर्ट के अनुसार, बाजार में रबी की अधिक सप्लाई और बांग्लादेश से आयात में मंदी के कारण घरेलू सप्लाई में वृद्धि के कारण प्याज की कीमतों में सालाना आधार पर 46 प्रतिशत की गिरावट आई है। बांग्लादेश भारत के प्याज निर्यात में 40 प्रतिशत का योगदान देता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बंगाल चना, पीली मटर और काले चने के आयात में वृद्धि के कारण दालों की कीमतों में 16

प्रतिशत की गिरावट आई है। उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम करने के लिए इन आयातों को मार्च 2026 तक अनुमति दी गई है।

तेल की कीमतों में बढ़त- फेस्टिव सीजन की शुरुआत में अधिक मांग के कारण वनस्पति तेल की कीमतों में सालाना आधार पर 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई और एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में सालाना आधार पर 6 प्रतिशत की वृद्धि के कारण थालियों की कुल लागत में भारी गिरावट आई।

मांसाहारी थाली की कीमत में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी रही, क्योंकि ब्रॉयलर की कीमतों में सालाना आधार पर 1 प्रतिशत की

मामूली गिरावट आई, जो इसकी लागत का लगभग 50 प्रतिशत है। वहीं, सब्जियों और दालों की कम कीमतों ने इस गिरावट को सपोर्ट दिया।

खरीफ की रोपाई में हुई देरी- क्रिसल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर पुशन शर्मा ने कहा, आगे चलकर, मध्यम अवधि में प्याज की कीमतों में मामूली वृद्धि देखी जा सकती है क्योंकि कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में अगस्त और सितंबर में अत्यधिक वर्षा के कारण खरीफ की रोपाई में देरी हुई है और उपज से जुड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं।

मुझसे ज्यादा काम करते हैं भारत के कर्मचारी...



नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत में काम के घंटों को लेकर खूब बहस होती है। कोई 70 घंटे काम करने की बात कहता है तो कोई 50 तो कोई 40 घंटे। भारतीय कर्मचारियों के काम को लेकर सवाल उठाने वाले भारतीय ही रहे हैं। लेकिन अब एक जापानी ने शायद सच बोल दिया है। जापान से भारत आए रेजी कोबायाशी यहीं अपना बिजनेस चलाते हैं। वह भारत में अपने अपने माइक्रो फाइनेंसिंग स्टार्टअप हक्री का विस्तार करने के लिए बंगलुरु से ही अपने बिजनेस को एक नया आयाम दे रहे हैं। उनका कहना है कि भारत, जापान की तुलना में स्टार्टअप के लिए अधिक गतिशील और स्वागत योग्य वातावरण प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग उनसे ज्यादा काम करते हैं।

बिजनेस इनसाइडर से बात करते हुए, जापानी एंटरप्रेन्योर रेजी कोबायाशी ने कहा कि भारत का आकार और ऊर्जा इसे अगला तार्किक कदम बनाती है। उन्होंने कहा, 'अफ्रीका में 1.4 अरब लोग हैं, लेकिन वे बिखरे हुए हैं। भारत में 1.3 अरब लोग हैं और अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है।'

गाड़ी खरीदने के लिए फाइनेंस की सर्विस देने वाली उनकी कंपनी हक्री ने केन्या में 3,500 से ज्यादा कारों को फंड किया है। कंपनी के अब भारत में चार, केन्या में 74 और दक्षिण अफ्रीका में दो कर्मचारी हैं। इसका मुख्यालय जापान में बना हुआ है, जहां से इसकी अधिकांश धनराशि जुटाई गई है।

इस IPO में गड़बड़ी है! प्रमोटर पर केस और गिरवी रखे शेयरों की बिक्री, लगे गंभीर आरोप, क्या आपने लगाया है पैसा?



नई दिल्ली (एजेंसी)। वी वर्क इंडिया के आईपीओ की सब्सक्रिप्शन की आज आखिरी तारीख है। इस बीच एक प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म इनगवर्न ने इस कंपनी के आईपीओ को लेकर चिंता जताई है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, इनगवर्न के फाउंडर श्रीराम सुब्रमण्यन ने बताया कि आईपीओ का ढाँचा- बिना किसी नई पूंजी निवेश के फुल ऑफर फॉर सेल

सिक्युरिटी ट्रांज़ैक्शन टैक्स संवैधानिक है भी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनाई; केंद्र सरकार को नोटिस जारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। काफी समय से निवेशकों के बीच शेयर, म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव के खरीद और बिक्री पर लगाया जाने वाला स्क्वॉज टैक्स चर्चा में रहा। अब इसको लेकर भारत के सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर की गई है। सोमवार 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिक्युरिटी ट्रांज़ैक्शन टैक्स की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की जांच करने का फैसला लिया है।

यह वित्त अधिनियम, 2004 के तहत लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज के जरिए से एक्सचेंज ट्रांज़ैक्शन पर लगाया जाने वाला डायरेक्ट टैक्स है।

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने असीम जुनेजा द्वारा दायर याचिका पर वित्त मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार को औपचारिक नोटिस जारी किया।

जुनेजा का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता सिद्धार्थ के. गर्ग ने किया। याचिका में तर्क दिया गया कि स्क्वॉज समानता, व्यापार या आजीविका कमाने के मौलिक अधिकारों और सम्मान के साथ जीने के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है।



याचिका में स्पष्ट किया गया कि स्क्वॉज को चुनौती इसलिए नहीं दी गई है कि शेयर बाजार प्रतिभागियों पर टैक्सेशन बढ़ गया है या वर्तमान में टैक्स अधिक है। याचिका में कहा गया है, वर्तमान याचिका SIT के रूप में लगाए गए टैक्स की वैधता पर सवाल उठा रही है... सबसे पहले, यह कि दो बार टैक्स भरने के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। उदाहरण के रूप में बाजार से कमाए गए फायदे पर पहले ही लाभ कर का भुगतान करता है और फिर उसे उसी लेनदेन पर पहले से चुकाए गए पूंजीगत लाभ कर के अलावा स्क्वॉज का भी भुगतान करना पड़ता है।

90 लाख डॉलर की कथित टैक्स चोरी, घरे में अदाणी ग्रुप की डिफेंस कंपनी, मिसाइल पार्ट्स के आयात से जुड़ा है मामला

नई दिल्ली (एजेंसी)। अदाणी ग्रुप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अधिकारी मिसाइल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों पर इंपोर्ट ड्यूटी चोरी के आरोप को लेकर अदाणी एंटरप्राइजेज की डिफेंस यूनिट, अदाणी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज की जांच कर रहे हैं। इस मामले की सीधे जानकारी रखने वाले दो सरकारी सूत्रों ने यह बताया है। यह अदाणी समूह के खिलाफ नई नियामक जांच का संकेत है।

अदानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज, मुख्यतः भारतीय सेना व



सुरक्षाबलों के लिए मिसाइल, ड्रोन और छोटे हथियार जैसे डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाती है। भारत के डायरेक्टरेट रेवेन्यू ऑफ डिफेंस

इंटेलेजेंस ने मार्च में अदाणी डिफेंस की जांच शुरू की थी, क्योंकि उसने कुछ मिसाइल घटकों के आयात में 77 करोड़ रुपये (90 लाख डॉलर) के टैरिफ की चोरी की थी। यह चोरी गलत तरीके से यह दावा करके की गई थी कि ये मिसाइलें सीमा शुल्क और कर से मुक्त हैं।

कथित कर चोरी की राशि 90 लाख डॉलर है। यह रकम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अदाणी डिफेंस के 2024-25 के 7.6 करोड़ डॉलर के राजस्व

का 10% से ज्यादा और उसके लाभ के आधे से भी ज्यादा है। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि जांच के दौरान अदाणी के अधिकारियों ने आयातित पुर्जों के गलत वर्गीकरण की बात स्वीकार की, लेकिन विस्तार से नहीं बताया।

दो सरकारी सूत्रों और रॉयटर्स ने इस मामले की जानकारी देने वाले एक दस्तावेज को खंगाला और इसके अनुसार, अदाणी समूह ने एक बयान में कहा कि निदेशालय ने कस्टम ड्यूटी नियमों की अपनी व्याख्या के आधार पर उसके आयातों पर 'स्पष्टीकरण मांगा था और सहायक दस्तावेजों के साथ इस पर सफाई दी गई है।

पंडित-मौलवी-पादरी नहीं इस महिला से बच्चों का नाम रखवा रहे लोग, ऐसा क्या खास जो 27 लाख तक फीस देने में भी नहीं हिचकिचाते

नई दिल्ली (एजेंसी)। पैसे कमाने के नए-नए बिजनेस आइडिया लोगों को मालामाल बना रहे हैं। एक महिला को भी एक नया आइडिया आया और उसने उसे अपना बिजनेस बना लिया। ये बिजनेस



आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है। मगर बिजनेस फिर बिजनेस है। ये बिजनेस है, बच्चों के नाम रखने का।

जी हां, अमीर माता-पिता अपने नन्हे-मुन्हे बच्चों के नामकरण में मदद के लिए एक 'प्रोफेशनल बेबी-नेमर' (बच्चों का नाम रखने वाली प्रोफेशनल) को हजारों डॉलर खर्च कर रहे हैं।

ऐसे हुई शुरुआत- अमेरिका की टेलर ए हम्फ्रे बच्चों के नाम रखने के लिए मोटी रकम चार्ज करती है। उन्होंने ने लगभग एक दशक पहले बच्चों के नामों के प्रति अपने जुनून को लेकर ऑनलाइन पोस्ट करना शुरू किया, जो कि अब उनका एक

शानदार बिजनेस बन गया है।

1980 के दशक की एक टीवी सीरियल अभिनेत्री टेलर मिलर के नाम पर हम्फ्रे का नाम रखा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हम्फ्रे के मुताबिक ये काम इतना आसान नहीं है, जितना लोग समझते हैं। उनके पास कभी-कभी ऐसे लोगों के फोन आते हैं, जो सब कुछ छोड़कर तुरंत उनकी सहायता चाहते हैं। सैन फ्रांसिस्को स्थित हम्फ्रे ने साल 2020 में 100 से ज्यादा बच्चों का नाम रखने में मदद की और 150,000 डॉलर (1.33 करोड़ रुपये) से ज्यादा की कमाई की। शुरुआत में वे इस सर्विस के लिए सिर्फ 1,500 डॉलर लेती थीं।

दैनिक हिन्दकुश

hindkush.in
24x7 News portal

सर्वे भवन्तु सुखिनः
उजैन, इंदौर, भोपाल से प्रकाशित

jagrayam.com
online news magazine

ऑनलाईन संवाददाता/ब्यूरो प्रतिनिधि चाहिए

हिन्दकुश मीडिया

hindkushmedia@gmail.com
jagrayam@gmail.com

कोल्ड्रफ के बाद दो और दवाएं बैन... विभाग ने Reshfysh TR सिरप की 134 शीशियां की जब्त

सिवनी। बच्चों की मौत का कारण बने कोल्ड्रफ व नेस्ट्रो डीएस सस्पेंशन सिरप पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही मप्र ड्रग कंट्रोलर ने 13 दवाओं की सैम्पल जांच में दो अन्य सिरप रिलाइफ तथा रेसफिकेश टीआर सिरप अवमानक पाया है। वयस्कों के उपयोग में होने वाले दोनों सिरप रिलाइफ व रेसफिकेश टीआर खरीदी-बिक्री पर पूरे राज्य में सरकार ने रोक लगा दी है।

विक्रय रोकने में संयुक्त टीमें जुटी-जिले के औषधि विभाग की टीम को निरीक्षण के दौरान एक थोक विक्रेता गुरुकृपा मेडिकल एजेंसी के पास रेसफिकेश टीआर सिरप की 134 शीशियों का स्टॉक मिला है, जिसे औषधि निरीक्षक मनीषा अहिरवार ने जब्त कर सैम्पल लेकर वापस निर्माण कंपनी को भेजा जा रहा है। इसी कंपनी के अलग-अलग बैच की लगभग 210 सिरप की शीशियों को फुटकर दवा विक्रेताओं को बीते दो-तीन माह में बेचा गया है, जिसे विभिन्न दवा दुकानों से जब्त कर इसके विक्रय रोकने में संयुक्त टीमें जुट गई हैं।

रिपोर्ट आने में एक सप्ताह का समय लगेगा-विक्रय करने अलग-अलग फुटकर दवा दुकानदारों द्वारा खरीदी गई प्रतिबंधित रेसफिकेश टीआर सिरप की शीशियों को जप्त करने संयुक्त टीमें मौके पहुंच रही हैं। वहीं 5 अक्टूबर को श्रीराम मेडिकल एजेंसी से जब्त प्रतिबंधित कोल्ड्रफ सिरप की



110 शीशियों को जब्त करने के बाद जांच के लिए सैम्पल प्रयोगशाला भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने में लगभग एक सप्ताह का समय लगेगा।

देर रात तक हुई जांच, एफडीसी के 6 सैम्पल एकत्रित किए-सोमवार को देर रात तक दवा दुकानों का ड्रग इंस्पेक्टर ने कलेक्टर के निर्देशन में गठित संयुक्त दल के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान फिक्स डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) वाली सिरप के 6 सैम्पल भी एकत्रित किए गए। सरकार की सख्ती के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में हड़कंप मच गया है। सुबह से लेकर देर रात तक

संयुक्त टीमें जांच व निरीक्षण करने में जुटी हैं, जो आगामी दिनों में भी जारी रहेगा। संयुक्त दल में नायब तहसीलदार, पुलिस अधिकारी, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, एसआई, टीआई, सहायक भू-अभिलेख अधीक्षक व अन्य ने 7 अक्टूबर को दोनों अवमानक औषधि का विक्रय रोकने संबंधित दवा दुकानों पर जाकर उपलब्ध स्टॉक वापस लौटाने व आगामी विक्रय बंद करने निर्देशित किया।

जांच में अवमानक पाए गए ये सिरप-ड्रग इंस्पेक्टर मनीषा अहिरवार ने बताया कि छिंदवाड़ा में सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के बाद विभिन्न किस्म की

दवाइयों के 13 नमूनों की जांच प्रयोगशाला में सरकार ने कराई है। इसमें वयस्कों में उपयोग दो कफ सिरप एम्बॉक्सोल एचसीएल, गुआइफेनेमिन, टयूटालिन, मथाल सिरप (रिलाइफ) व ब्रोमहेक्सीन हाइड्रोक्लोराइड, टयूटालिन, मुआइफेलेसिन व ममाल सिरप (रेसफिकेश टीआर) का सैम्पल जांच में अवमानक पाया गया है। ड्रग कंट्रोलर ने इन दोनों दवाओं की बिक्री व वितरण पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए।

दवा दुकानों में कहां कितना मिला स्टॉक- अवमानक पाई गई सिरप का स्टॉक दो थोक विक्रेताओं द्वारा रखा जाता है। रिलाइफ सिरप का स्टॉक जिले में किसी भी थोक विक्रेता के पास नहीं है।

रेसफिकेश टीआर का स्टॉक गुरुकृपा मेडिकल एजेंसी में मिला है। हेमंत ड्रग्स द्वारा रेसफिकेश टीआर का विक्रय फुटकर दवा विक्रेताओं को किया जा चुका है, जिसके पास स्टॉक नहीं पाया गया है।

ड्रग इंस्पेक्टर को निरीक्षण में गुरुकृपा मेडिकल एजेंसी में रेसफिकेश टीआर की 134 शीशी मिली है, जिसे जब्त कर वापस निर्माता कंपनी को भेजने तथा बेची गई लगभग 210 शीशी सिरप को वापस बुलाने के निर्देश गए हैं।

निरीक्षण में हेमंत ड्रग्स में प्रतिबंधित दवा का स्टॉक नहीं मिला है। यह सिरप हेमंत ड्रग्स एजेंसी ने भारत मेडिकल सिवनी, मातोश्री मेडिकल स्टोर केवलारी, मां श्यामा

मेडिकल केवलारी को बेचा है।

वहीं गुरुकृपा मेडिकल एजेंसी ने भारत मेडिकल स्टोर मलारा, राज मेडिकल स्टोर बखारी, वारानसी नाथ मेडिकोज पलारी, भारत मेडिकोज धारना सिवनी, ओम मेडिकल स्टोर भोमा, अमन मेडिकल स्टोर केवलारी, नीरज मेडिकल स्टोर केवलारी, कंचन मेडिकल छपारा को स्टॉक बेचना बताया है।

सभी फुटकर दवा विक्रेताओं को थोक विक्रेताओं से खरीदी गई सिरप का स्ट-क वापस लौटाने कहा जा रहा है। साथ ही रेसफिकेश टीआर का स्टॉक गुरुकृपा मेडिकल एजेंसी व हेमंत ड्रग्स को रिटेल केमिस्ट से स्टॉक वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं।

एफडीसी उत्पाद का उपयोग नहीं करने की चेतावनी-गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बलोफेनियमाइन मेलीएट 2 मिलीग्राम फिलाइनपकिन हाइड्रोक्लोराइड 5 मिलीग्राम फार्मूला वाले सभी उत्पादों पर एफडीसी का उपयोग न करने की चेतावनी लिखने के निर्देश दिए हैं। इस उत्पादों पर चेतावनी की लेवलिंग है या नहीं इसकी जांच भी दवा दुकानों का निरीक्षण कर रहा संयुक्त दल कर रहा है। लेबल पर चेतावनी न पाए जाने पर सिरप निर्माता फर्म को वापस भेजने हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

बाहरी को फायदा, एमपी वालों को कुछ नहीं... पुलिस भर्ती के नियम में बड़े बदलाव

भोपाल। एमपी पुलिस में आठ वर्ष बाद सूबेदार और उपनिरीक्षक के पदों पर भर्ती प्रारंभ होने से युवा खुश हैं तो इस बात से नाराज भी हैं कि अन्य राज्यों के युवाओं को भी प्रदेश के युवाओं की तरह अवसर दिए गए हैं। अधिकतम आयु सीमा प्रदेश व बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए बराबर रखी गई है।

प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय-इसके पहले हुई परीक्षा में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष और एमपी के अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 33 वर्ष होती थी। अब बाहर वालों के लिए भी 33 वर्ष की सीमा ही रखी गई है। उन्हें एमपी में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता, यानी वे यहां अनारक्षित श्रेणी में आवेदन करेंगे। 27 अक्टूबर शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

कर्मचारी चयन मंडल ने सोमवार को भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए 27 अक्टूबर से आवेदन किए जा सकेंगे। प्रारंभिक लिखित परीक्षा नौ जनवरी 2026 को होगी। सूबेदार के 28, विशेष सशस्त्र बल में उप निरीक्षक के 95 और जिला पुलिस बल व अन्य के 377 पदों को मिलाकर 500 पदों पर भर्ती हो रही है। इसके पहले वर्ष 2017 में भर्ती हुई थी। इसके बाद कोविड और फिर अन्य कारणों से भर्ती नहीं होने के कारण परीक्षा की तैयारी कर रहे डेढ़ लाख से अधिक युवा अधिकतम आयु सीमा पार कर गए। वे अनारक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा में दो वर्ष की छूट यानी 33 की जगह 35 करने की मांग कर रहे थे, पर सरकार ने नहीं माना।

प्रदेश के युवाओं का नुकसान-बता दें कि इसके पहले सरकार ने पुलिस की भर्तियों में रोजगार कार्यालय में पंजीयन की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इससे भी प्रदेश के युवाओं का नुकसान हुआ है। कारण, दूसरे राज्यों के युवा मध्य प्रदेश में पंजीयन कम कराते थे, जिससे वे आवेदन के समय अपात्र हो जाते थे।

कांग्रेस का आरोप- जहरीले कफ सीरप से बच्चों की मौत के लिए सरकार की लापरवाही जिम्मेदार

भोपाल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल में 17 बच्चों की जहरीले कोल्ड्रफ कफ सिरप से मौत के लिए कांग्रेस ने सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार बताया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में संयुक्त पत्रकार वार्ता करके आरोप लगाया है कि गत चार सितंबर को पहले बच्चे की मौत होने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार नहीं जागी। जहरीले सीरप की बात को नकारा जाता रहा। जब तमिल नाडु ने जांच कर जहरीले रसायन का उपयोग पाया, तब सरकार को हरकत में आना पड़ा।

दोनों कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 24 अगस्त को छिंदवाड़ा में फिटकुरिया का पहला बच्चा भर्ती हुआ। इसके बाद यह संख्या बढ़ती



जब्त हुई।

यह बताता है कि प्रदेश में नशे का नेटवर्क पुलिस की नाक के नीचे और राजनीतिक संरक्षण में पनप रहा है। कांग्रेस ने सरकार से दोषियों को सजा देने, जहरीली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने और बच्चों की सुरक्षा व पोषण पर गंभीरता से काम करने की मांग की।

कुपोषण की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक, चिकित्सा सेवा भगवान भरोसे- सिंघार ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के हाल बुरे हैं। इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल में दो नवजात को चूहों ने कुतर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। प्रदेश में कुपोषण दर 7.79 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 5.4 प्रतिशत से अधिक है।

जिला मुख्यालयों पर कैंडल मार्च-कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू

पटवारी ने भोपाल में पत्रकार वार्ता करके आरोप लगाया कि प्रदेश में कोल्ड्रफ कफ सीरप के कारण 19 बच्चों की जान चली गई और सात गंभीर हालत में हैं, इसके बाद भी कोई जिम्मेदार नहीं।

सरकार इतनी असंवेदनशील हो चुकी है कि उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य राजेंद्र शुक्ल और प्रभारी मंत्री राकेश सिंह, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य संदीप यादव छिंदवाड़ा पहुंचे तक नहीं।

मुख्यमंत्री मोहन यादव को इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन ड्रग कंट्रोलर को हटाने से कुछ नहीं होगा, उनके विरुद्ध तो एफआईआर होनी चाहिए।

कांग्रेस ने तय किया है कि नौ अक्टूबर को ब्लाक और जिला मुख्यालयों पर कैंडल मार्च निकालकर दिवंगत बच्चों को श्रद्धांजलि देने के साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी।



नर्सरी एवग्रिन

लैंड स्केपिंग, प्लान्टेशन डेवलपर्स

62, विश्वविद्यालय मार्ग, मिशन कम्पाउंड, उज्जैन मो. 9827381730

राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में सुनिश्चित करने के लिए निर्देश



इंदौर। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय समन्वय समिति एवं समय-सीमा पत्रों (टीएल) की समीक्षा बैठक कलेक्टर कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राजस्व प्रकरण में गति लाते हुए, उन्हें निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करें। साथ ही महिला एवं बाल

विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, गृह विभाग, सहकारिता विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, लोक निर्माण विभाग, श्रम विभाग, ऊर्जा विभाग आदि विभागों के लंबित प्रकरण भी समय-सीमा में निराकरण करना सुनिश्चित करें। बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आमजन से जुड़ी शिकायतों एवं योजनाओं

के प्रकरण के समाधान में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में अपर कलेक्टर श्री नवजीवन विजय पंवार, श्री रोशन राय, श्री रिकेश वैश्य, जिला पंचायत सीईओ श्री सिद्धार्थ जैन, एमपीआईडीसी के कार्यकारी निदेशक श्री हिमांशु प्रजापति, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव हसानी, जिला आपूर्ति एवं खाद्य नियंत्रक श्री एमएल मारू सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सोयाबीन खरीद भावांतर योजना की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए- बैठक में कलेक्टर श्री वर्मा ने सभी अपर कलेक्टरों, अनुविभागीय अधिकारियों सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सोयाबीन खरीद भावांतर भुगतान योजनातंत्रित किसानों का पंजीयन ई-उपाजर्न पोर्टल पर किया जाए। पंजीयन पीएसीएस/सीएससी/ एमपी किसान ऐप के माध्यम से कराये जाए। भावांतर योजना की

जानकारी सभी कृषि उपज मंडियों में होर्डिस एवं बैनर के माध्यम से दी जाए। इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। मंडियों एवं विक्रय केन्द्रों पर किसानों के बैठने के लिए छायादार टिन शेड लगाये जाए। साथ ही पीने के पानी एवं बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। पार्किंग की व्यवस्था सहित किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाये जाए। पीओएस मशीनों की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही कम्प्यूटर ऑपरेटरों की संख्या में वृद्धि की जाए, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़े। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने कहा कि प्रत्येक मंडी के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति, योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए व्यापारी के स्टॉक की उपलब्ध रियल टाइम जानकारी का समय-समय पर सत्यापन, मॉडल रेट की सतत निगरानी जिससे कि अनावश्यक गिरावट न हो और भावांतर योजना के तहत खरीदे गए सोयाबीन का भुगतान बैंक खातों में सुनिश्चित किया जायेगा।

सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी

के मामलों पर दिखाई सख्ती- बैठक में कलेक्टर श्री वर्मा ने विभागवार सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वे बैठक में पूर्व तैयारियों के साथ आए और प्रत्येक निर्देश को नोट करें। काम नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी अपर कलेक्टरों को निर्देशित किया कि वे अपने अधीनस्थ विभागों की व्यक्तिगत मॉनिटरिंग करें।

इंदौर को रैंकिंग में टॉप जिलों में बनाये रखें- बैठक में कलेक्टर श्री वर्मा ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे पारदर्शिता, समन्वय और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। सीएम हेल्पलाइन के तहत शासन की रैंकिंग में इंदौर को टॉप जिलों की सूची में बनाये रखना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है, इसके लिए सभी विभाग लंबित प्रकरणों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें। योजनाओं का क्रियान्वयन समय-सीमा में हो और नागरिकों की समस्याओं के प्रति गंभीरता हो।

औषधि नियमों के उल्लंघन पर अपना मेडिकल स्टोर परासिया का ड्रग लाइसेंस निरस्त

इंदौर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय छिंदवाड़ा द्वारा विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर जिले के परासिया स्थित अपना मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी श्री शरद कुमार जैन ने बताया है कि आदेश के पश्चात इस मेडिकल स्टोर्स द्वारा अब दवाओं का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन पर तीन से पाँच वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।

अनुज्ञापन अधिकारी श्री जैन ने बताया कि विभिन्न बिंदुओं पर अपना मेडिकल स्टोर्स परासिया का निरीक्षण किया गया, जिसमें औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के तहत गंभीर अनियमितताएँ पाई गईं। निरीक्षण के दौरान विक्रय रिकॉर्ड अपूर्ण पाए गए, पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाओं का विक्रय किया जा रहा था तथा विक्रय बिल प्रस्तुत नहीं किए गए। इन उल्लंघनों के संबंध में औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, किन्तु नियत अवधि में संचालक द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त के दृष्टिगत अपना मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

इंदौर जिले में भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान सख्ती से क्रियान्वित किया जाएगा: कलेक्टर

इंदौर। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा की अध्यक्षता में भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान को लेकर कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इंदौर जिले में पुनः भिक्षावृत्ति शुरू नहीं हो, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाए। विशेषकर बड़ा गणपति, रेलवे स्टेशन, सत्य साईं चौराहा, विभिन्न मठ-मंदिरों, आश्रमों एवं सार्वजनिक स्थानों पर जहां भिक्षावृत्ति की जाती है, उसे सख्ती से रोका जाए। इसके लिए विशेष रेस्क्यू टीमें बनायी जाए, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग, नगर निगम, होमगार्ड, श्रम विभाग, राजकीय बाल संरक्षण आश्रम के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हो। साथ में विशेष पुलिस किशोर इकाई के अधिकारी और

कर्मचारियों को भी इस टीम में शामिल किया जाए। ऐसी दो-तीन टीमें शहर में अलग-अलग स्थानों पर लगातार कार्रवाई करें, ताकि कहीं भी भिक्षावृत्ति नहीं हो। भिक्षा मांगना भी अपराध है और भिक्षा देना भी इसी श्रेणी में आता है। जो लोग भिक्षावृत्ति की सूचना देते हैं, ऐसे लोगों को नगद इनाम देकर पुरस्कृत किया जाए।

कलेक्टर श्री वर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि भिक्षावृत्ति करने वालों को रोकना ही नहीं, उन्हें आजीविका से जोड़ने के लिए भी योजनाएं बनायी जाए। उन्होंने आगे कहा कि भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए रेस्क्यू करने वाली टीमें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिन लोगों ने पूर्व में भिक्षावृत्ति छोड़ दी क्या वे पुनः इसी क्षेत्र में वापस आ रहे हैं।

जो लोग विशेषकर किशोर एवं युवा नशा करते हैं या वे अपराधी प्रवृत्ति के हैं, ऐसे लोग भी भिक्षावृत्ति के क्षेत्र में बड़ी संख्या में सलिस है। ऐसे असामाजिक और अपराधिक लोगों को सुधार गृह में भेजा जाये और उनकी बेहतर काउंसलिंग की जाए। सार्वजनिक स्थानों पर लिखे-बच्चों को भीख नहीं, सीख दीजिए-, आओं मिलकर भिक्षावृत्ति मुक्त इंदौर बनाए। भिक्षावृत्ति रोकने के लिए गली एवं चौराहों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रचार किया जाए। इस कार्य में समाज सेवा महाविद्यालय इंदौर के छात्र-छात्राओं एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं के युवाओं को जोड़ा जाए।

बैठक में अपर कलेक्टर श्री नवजीवन विजय पंवार, श्री रोशन राय, श्री रिकेश वैश्य, जिला पंचायत सीईओ श्री सिद्धार्थ जैन,

एमपीआईडीसी के कार्यकारी निदेशक श्री हिमांशु प्रजापति, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव हसानी, महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री रजनीश सिन्हा, श्रम विभाग की अधिकारी श्रीमती मेघना भट्ट सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में राजकीय बाल संरक्षण आश्रम के अधीक्षक श्री दिनेश मिश्रा ने बताया कि इंदौर शहर में भिक्षावृत्ति रोकने के लिए जिला प्रशासन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग एक विशेष चलाया था, जिसमें दल को विशेष सफलता मिली। इस दल ने पाया कि इंदौर में भिक्षावृत्ति करने वालों की संख्या 6 हजार 500 लोगों से अधिक है, जिसमें बच्चे, किशोर युवाओं से लेकर वृद्धजन तक शामिल है।

दिव्यांग बच्चों की त्वरित पहचान हेतु स्क्रीनिंग शिविरों के आयोजन का सिलसिला जारी

इंदौर। राज्य शासन के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा इंदौर जिले में जुवेनाइल जस्टिस कमेटी हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश की अनुशांसा के परिपालन में 15 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों की त्वरित पहचान हेतु स्क्रीनिंग शिविरों के आयोजनों का सिलसिला जारी है। इंदौर जिले में विभिन्न निकायों/संस्थाओं में कुल 12 केंद्रों का आयोजन करने हेतु केलेण्डर जारी किया गया है। अभी तक संपन्न हुए केंद्रों में स्क्रीनिंग हेतु दिव्यांग बच्चों की संख्या अत्यधिक कम परिलक्षित होने से कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश

दिए हैं कि केंद्रों में दिव्यांग बच्चों की उपस्थिति अधिक से अधिक सुनिश्चित किया हो। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, विशेष शिक्षकों को भी निर्देशित किया गया है कि वे दिव्यांग बच्चों की केम्प में अधिक से अधिक उपस्थिति सुनिश्चित करें, ताकि आने वाले विषय विशेषज्ञों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो। संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण ने बताया कि एक केम्प में 50 बच्चों को सम्मिलित करवाने पर 10 हजार रूपये, उससे अधिक बच्चे सम्मिलित करवाने पर 20 हजार रूपये आवागमन का व्यय दिया जायेगा।

इंदौर में राज्य सूचना आयुक्त ने शिविर लगाया, 55 प्रकरणों में 44 अपीलार्थी हुए उपस्थित

इंदौर। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. उमाशंकर पचौरी ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय इंदौर में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत शिविर आयोजित किया। साथ ही जिले के लोक सूचना अधिकारियों व प्रथम अपीलीय अधिकारी की बैठक भी की। जिले के विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारियों के साथ सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में डॉ.पचौरी ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने में लोक सूचना अधिकारियों का महत्वपूर्ण स्थान है। सूचना का अधिकार आम नागरिकों के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता की महत्वपूर्ण कड़ी है। नागरिकों को समय पर, सटीक और पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना सभी लोक सूचना अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। डॉ. पचौरी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी



स्तर पर सूचना में विलंब या अपूर्ण जानकारी देना अधिनियम की भावना के विपरीत है। उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि आमजन को समय पर और पारदर्शी तरीके से सूचना उपलब्ध कराना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सूचना तक जाना हर व्यक्ति का

जानकारी रखते हुए कार्य करें तो नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि लंबित आवेदनों का समयबद्ध निराकरण किया जाए और आवेदकों को अनावश्यक रूप से इधर-उधर भटकने की स्थिति में न रखा जाए।

अधिकार है। बिना पढ़े-लिखे आम आदमी को भी आसानी से जानकारी मिले, यही सूचना के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है। राज्य सूचना आयुक्त ने अधिकारियों को नागरिकों की शिकायतों और आवेदनों के प्रति उत्तरदायी बने रहने पर बल दिया।

डॉ. पचौरी ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव हैं। अधिकारी यदि नियमों और प्रक्रिया की पूरी

एक दिवसीय रोजगार मेला 13 अक्टूबर को

इंदौर। राज्य शासन के निर्देशानुसार इंदौर जिले के बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कर्पणियों में रोजगार दिलाने के लिए नियमित रूप से रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित हो रहे हैं। इसी सिलसिले में आगामी 13 अक्टूबर को सुबह 10.30 बजे से एक दिवसीय रोजगार मेले (युवा संगम कार्यक्रम) का आयोजन किया गया है। यह मेला जिला रोजगार कार्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था और जिला उद्योग केन्द्र इंदौर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होगा। मेले का आयोजन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नन्दा नगर इन्दौर में किया जा रहा है। उप संचालक रोजगार श्री पी.एस. मंडलोई ने बताया कि इस मेले में जहां एक ओर युवाओं को प्रतिष्ठित क्षेत्र की निजी कर्पणियों में नौकरी दिलाई जाएगी, वहीं दूसरी ओर खुद का व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को लोन के लिए मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित कर्पणियां जैसे- Medplus India, JUMD SkillTech Private limited, Just Dial, Aisect, INFINITY FABTECH PRIVATE LIMITED, Coderwing, रूपरंग स्टोर्स आदि के 350 से अधिक रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रारम्भिक रूप से चयन हेतु उपस्थित रहेगी। जिसमें बैंक ऑफिस, कम्प्यूटर ऑपरेटर, फार्मासिष्ट, सैल्स, बीपीओ, हैप्पर, डिजिटल मार्केटिंग तथा टेक्नीशियन जैसे फिटर/इलेक्ट्रीशियन/ टर्नर/ मशीनिष्ट, वैल्डर आदि विभिन्न पदों हेतु साक्षात्कार लेकर चयन किया जाएगा। उक्त मेले में 18 से 40 वर्ष के आवेदक जो की पांचवी से लेकर सत्रात्कोत्तर किसी भी विषय में पास एवं तकनीकी योग्यता जैसे आईटीआई के आवेदक भी उक्त पदों हेतु रोजगार मेले में भाग लेकर योग्यता अनुसार रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार मेले में सम्मिलित होने वाले आवेदक अपनी समस्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों के साथ बायोडेटा की प्रतियों एवं अन्य प्रमाण पत्र जैसी आधार कार्ड आदि के प्रमाणपत्रों की फोटो प्रतियों भी आवश्यक रूप से साथ लावें।

कलेक्टर की अध्यक्षता में एमपीआईडीसी द्वारा औद्योगिक संस्थाओं को जमीनों की आवंटन प्रक्रिया को लेकर बैठक आयोजित

इंदौर। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा की अध्यक्षता में एमपीआईडीसी द्वारा औद्योगिक संस्थाओं को जमीनों की आवंटन प्रक्रिया को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एमपीआईडीसी द्वारा औद्योगिक संस्थाओं को दी जा रही जमीनों की प्रक्रिया में गति लाये, जो प्रकरण तहसील स्तर पर लंबित है उसका त्वरित निराकरण करें।

जय श्री महाकाल ...



वन्दे देव उमापतिम सुरगुरुं वन्दे जगत् कारणं, वन्दे पन्नग भूषणं मृधरम
वन्दे पशुनाम्पतिम, वन्दे सूर्य शशांक वहिनयनम वन्दे मुकुदप्रियम,
वन्दे भक्त जनाश्रयम च वरदम वन्दे शिवम शंकर !
भूतभावन बाबा श्री महाकालेश्वर भगवान सभी को आरोग्यता प्रदान करें ।

महाकाल क्षेत्र में सौंदर्यीकरण और नए आवासीय-वाणिज्यिक प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी

यूडीए बोर्ड की बैठक में शहर के लिए 400 करोड़ के विकास कार्यों को मिली मंजूरी

उज्जैन। उज्जैन विकास प्राधिकरण (यूडीए) के संचालक मंडल की बैठक सोमवार को संभागायुक्त एवं प्राधिकरण अध्यक्ष आशीष सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में शहर के विकास और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए।

बैठक में कालिदास अकादमी परिसर में 7.29 करोड़ रुपए की लागत से विशाल डोम और शेड निर्माण को मंजूरी दी गई। यह डोम श्री भरत विशाला रंगमंच के सामने बनेगा, जिससे सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आयोजनों के लिए आधुनिक मंच उपलब्ध होगा।

400 करोड़ के विकास कार्यों को स्वीकृति

यूडीए की योजनाएं क्रमांक टीडीएस-03, 04, 05 और 06 के



तहत लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।

वहीं, नानाखेड़ा बस स्टैंड के सामने समुद्र मंथन चौराहे पर 56 करोड़ रुपए की लागत से वाणिज्यिक सह आवासीय कॉम्प्लेक्स के निर्माण को मंजूरी दी गई। इस प्रोजेक्ट से शहर को आधुनिक व्यवसायिक स्वरूप मिलेगा और व्यापारिक गतिविधियों को नया आयाम

मिलेगा।

आवास योजना और सिंहस्थ तैयारी

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ईडब्ल्यूएस श्रेणी) के तहत 500 फ्लैट्स के निर्माण हेतु भूमि चिह्नित किए जाने की स्वीकृति दी गई।

सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए 11 प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण

के लिए निविदाएं स्वीकृत की गईं। इसके साथ ही मंगलनाथ परिसर में 8.10 करोड़ रुपए की लागत से स्टोन क्लैडिंग, और महाकाल मंदिर परिसर के विभिन्न प्रवेश द्वारों पर कार्ट आयरन गेट व शेड सहित सौंदर्यीकरण कार्यों को भी मंजूरी दी गई।

गुणवत्ता पर विशेष ध्यान

विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बैठक में पीएमसी कंसल्टेंट, रोड सेफ्टी ऑडिटर, इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट तथा ट्रांजेक्शन एडवाइजर की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके अलावा, हरीफाटक रोड स्थित यूनिटी मॉल के पास की भूमि को नगर विकास योजना-13 के अंतर्गत विकसित करने का निर्णय भी लिया गया।

शरद पूर्णिमा की चाँदनी रात में अमृत वर्षा के साथ ही दमा रोग की चिकित्सा की गई

उज्जैन। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर डॉ. प्रकाश जोशी एवं समस्त आयुर्वेद महाविद्यालय के विद्यार्थियों के संयुक्त तत्वावधान में 28वां शरद पूर्णिमा



आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन इंदिरा नगर उज्जैन में किया गया। इस अवसर पर 800 से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कैंप में दमा (अस्थमा) तथा अन्य श्वसन संबंधित रोगों के लिए विशेष औषधियाँ निःशुल्क प्रदान की गईं। रोगियों को आयुर्वेद सिद्धांतों के अनुसार ऋतु एवं प्रकृति के अनुरूप जीवनशैली अपनाने के

लिए प्रेरित किया गया। साथ ही आयुर्वेद के विशेषज्ञों ने व्यक्तिगत परामर्श भी दिया। डॉ. प्रकाश जोशी ने बताया कि शरद पूर्णिमा को आयुर्वेद में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण तेज के साथ धरती पर अमृत तुल्य किरणें बरसाता है, जो शरीर में शीतलता एवं संतुलन प्रदान करती है। दमा जैसे रोगों में जहाँ पित्त एवं कफ का असंतुलन प्रमुख कारण

होता है, वहीं शरद पूर्णिमा की रात्रि में सेवन की जाने वाली औषधियाँ विशेष रूप से प्रभावी होती हैं। इस दिन तैयार औषधियाँ अधिक शक्तिशाली मानी जाती हैं, क्योंकि चंद्र किरणों का स्पर्श

उन्हें शीतल, स्निग्ध एवं पित्तशामक गुण प्रदान करता है।

आयुर्वेद के अनुसार इस दिन चंद्रकिरणों में सोमरस (अमृत तत्व) की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर, मन और आत्मा - तीनों को संतुलित करता है। इस रात औषधि युक्त खीर वितरित की गई तथा प्रातः 6 बजे से कर्णवेधन चिकित्सा का लाभ भी रोगियों को प्राप्त हुआ।

शरद पूर्णिमा पर बसंत विहार में हुए गरबे, 221 लीटर केसरिया दूध का किया वितरण



उज्जैन। शरद पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में बसंत विहार कॉलोनी में गरबे का आयोजन किया गया जिसमें मातृशक्तियों एवं बच्चियों ने सैकड़ों की संख्या में गरबे की प्रस्तुति दी। साथ ही 221 लीटर केसरिया दूध वितरण जनसहयोग से किया गया। केसरिया दूध वितरण कार्यक्रम में कॉलोनी के बच्चे, बच्चियाँ, गणमान्य नागरिक एवं मातृशक्तियाँ ने सहभागिता कर कार्यक्रम को सफल बनाया।

अद्भुत सम्मान, सीना 56 इंच से बढ़कर संघ की उम्र समान 100 इंच का हो गया- राजकुमार परसवानी



उज्जैन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (1925 से 2025) शताब्दी वर्ष के अवसर पर तीन किलोमीटर लंबे रास्ते पर निकले पथ संचलन को लेकर नगरवासियों में जो उत्साह था उसका वर्णन शब्दों में बयां नहीं कर सकते। जो पथ संचलन में चले थे, जिन्होंने स्वयंसेवकों को संघ की धुन पर कदमताल मिलाते हुए, अनुशासन में चलते हुए देखा, वहीं इसका अनुभव कर सकते हैं। सैकड़ों जगह पुष्प वर्षा, आरती कर, स्वागत किया, सेवा भारती की कन्याओं द्वारा, कतारबद्ध खड़े होकर बड़ी संख्या में आरती की, थाली लेकर स्वागत किया गया। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए, स्वागत किया गया।

राजकुमार परसवानी ने बताया कि मैं बाल्य काल से संघ का स्वयंसेवक हूँ। संत नगर बस्ती का उप प्रमुख का दायित्व है। मैंने 63 वर्ष की उम्र में दिल से किया गया, निःस्वार्थ भाव से ऐसा सम्मान नहीं देखा। लाखों रुपए खर्च कर जो सम्मान नहीं मिलता, वह हमें मिला, नगरवासियों ने स्वयंसेवकों का स्वागत कर जो, अभिवादन किया, जिससे हर संघ वालों का, सीना 56, इंच से बढ़कर संघ की उम्र समान 100 इंच का हो गया। राजकुमार परसवानी ने कहा इस सम्मान के लिए हम नगरवासियों के, संघ के आभारी हैं।

राष्ट्र सेविका समिति का पथ संचलन 12 अक्टूबर को, अभ्यास प्रारंभ

उज्जैन। राष्ट्र सेविका समिति द्वारा 12 अक्टूबर रविवार को पथ संचलन निकाला जाएगा। जिस हेतु अभ्यास कार्यक्रम 7 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ। प्रतिदिन शाम 4 बजे से 6 बजे तक क्षीरसागर उद्यान में बहनों को अभ्यास कराया जाएगा।

राष्ट्र सेविका समिति की दीपा पांडे एवं रेखा मेहता ने बताया कि 12 अक्टूबर रविवार को सायं 4 बजे क्षीर सागर उद्यान से पथ संचलन निकलेगा। जो बहनें पथ संचलन में अपनी उपस्थिति देने वाली हैं उन सभी से अभ्यास कार्यक्रम में आवश्यक रूप से उपस्थित होने का अनुरोध किया है। समिति ने कहा अभ्यास से ही गुणवत्ता में सुधार होगा अतः सभी के लिए अभ्यास में आना आवश्यक रहेगा। राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं।

शरद पूर्णिमा पर मत्स्येंद्रनाथ समाधि पर 751 लीटर खीर का भोग लगाया

उज्जैन। योगिराज मत्स्येंद्रनाथ समाधि संरक्षण, विकास एवं शरदोत्सव समिति द्वारा शरद पूर्णिमा पर समिति के अध्यक्ष प्रकाश रघुवंशी की अध्यक्षता में भव्य कार्यक्रम किया गया।

6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के अवसर पर गढ़कालिका मंदिर के आगे शिप्रा किनारे स्थित मत्स्येंद्रनाथ समाधि स्थल पर वर्षों पुरानी परम्परा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। शाम 7 बजे भव्य जुलूस रामप्रसाद चौहान व अजजू पटेल के नेतृत्व में पीपलीनाका हनुमान मंदिर से शुरू होकर समाधि स्थल पर पहुंचा। रात्रि 10:30 बजे मत्स्येंद्रनाथजी की समाधि पर चादर चढ़ाई गई व महाआरती एवं अमृत रूपी खीर प्रसादी का वितरण किया गया जिसमें मुख्य अतिथि राज्यसभा



सांसद उमेशनाथ महाराज, गुरु महावीरनाथजी, राघवेंद्रदास महाराज, दिग्विजय दासजी महाराज एवं विशेष अतिथि, पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक पारस जैन, पूर्व निगम सभापति सोनू गेहलोत, विजय पटेल

एडवोकेट, पारस गेहलोत, पार्षद गब्बर भाटी, भूरू काका भाटी, पार्षद सपना सांखला, शील लश्करी, जयंत गरुड, मुकेश जोशी व क्षेत्रीय एवं समस्त पूज्य साधु सतों व समस्त उज्जैन शहर के

गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ है जिसमें शहरवासी व योगिराज मत्स्येंद्रनाथ समाधि संरक्षण, विकास एवं शरदोत्सव समिति के सदस्य विशेष रूप से राधेश्याम गेहलोत पहलवान, रामप्रसाद चौहान, सत्यनारायण कछवा, किशोर कुमार भाटी, अजजू पटेल, अभिषेक देवड़ा, मोहन राठौर, पंकज जादम, अजय गेहलोत, रमेश खलीफा, मंगल कछवा, मानक मारोडिया, शंकरलाल दगदी, प्रेम गेहलोत, रामकृष्ण पाठक, गोपाल कृष्ण नामदेव आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का आभार अजय गेहलोत ने किया। जानकारी मनोहर गेहलोत द्वारा दी गई।